

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

संo 424]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1977/पौष 10, 1899

No. 424]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1977/PAUSA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 1977

G.S.R. 798 (E).—The following Proclamation by the President is rublished for general information.

Whereas, I. Neelam Sanjava Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Karnataka and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation namely —
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be

- lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State.
- (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:
 - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
- so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India.

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

- so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
- clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article; article 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto;

article 185;

- so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;
- so much of article 188 as relates to a member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive),

clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

- the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
 - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
- (iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved:
- (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the function and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:
 - Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, article 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and

paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State:

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Mysore General Clauses Act, 1899 (Mysore Act No. III of 1899) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or Law as if it were an Act of the Legislature of the State

NEELAM SANJIVA REDDY.

NEW DELHI;

President.

The 31st December, 1977.

[No. F. V/11013/33/77-S&P(DV)]

T C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

NEW DELHL

The 31st December, 1977.

गृह मंत्रालय

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

सा॰ का॰ नि॰ 798 (म). -- राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है:--

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपित, नीलम संजीव रेड्डी को कर्नाटक राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है थ्रौर मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट थ्रौर घन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई है कि जिसमे कि उस राज्य का शासन भारत के सविधान (जिसे इसमे इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबन्धों के ध्रनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

म्रत[.] म्रज मैं, सविधान के भ्रमुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त भुझे समर्थ बनाने वाली भ्रन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतक्द्वारा उद्घोषणा करता क्रुं कि मैं.—

- (क) उक्त राज्य की मरकार के सभी कृत्य श्रीर उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप मे स्वयं सम्भालता हुं;
- (ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विद्यान मण्डल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के मधीन प्रयोक्तक्य होंगी ; म्रीर

- (ग) निम्नलिखित मानुषगिक मौर पारिणामिक उपबन्ध करता हू जो इस उद्घीषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मझे ग्रावश्यक या बांछनीय प्रतीत होते है, अर्थात्--
 - (i) इस उद्घोषणा के उपर्यक्त खण्ड (क) के श्राधार पर मेरे द्वारा सम्भाक्षे गए कृत्यों ग्रौर शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक कि मैं ठीक समझ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम मे कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;
 - (ii) उक्त राज्य के सम्बन्ध मे मिवधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतदुद्वारा निलम्बित किया जाता है, ग्रथीत् .---
 - श्रन्च्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निदेश करने से है;
 - श्रनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियन्नक श्रौर महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समग्र प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनो को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है ;

भनुच्छेद 163 भीर 164 ;

श्रनुच्छेद 166 का खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध मंत्रियों के बीच राज्य सरकार के काम के प्रावटन से है;

श्रनुच्छेद 167 ;

श्रन्च्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा सकल्प को पारित करने से हैं;

म्रन्च्छेद 174 का खण्ड (1) भीर खण्ड (2) का उप-खंड (क) ;

भ्रनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमे ये दोनो सम्मिलित हैं) ;

भ्रनच्छेद 179 के खण्ड (ख) भ्रीर (ग) भ्रीर उस भ्रनुच्छेद का प्रथम परन्तुक ,

भ्रनुच्छेद 180, 181 भ्रौर 182, भ्रनुच्छेद 183का खण्ड (ग) भ्रौर उसका परन्तुक ;

म्रानुच्छेद 185;

भ्रनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों धौर भत्तो से है;

ग्रनच्छेद 188 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के सदस्य से हैं ;

अनुच्छेद 189, 193 **औ**र 194 ;

मनम्छेद 195 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के सदस्यों के वैतनो श्रीर भत्तो से है ;

श्रनण्छेद 196 से 198 तक (जिसमे ये दोनों सम्मिलित हैं) ; धन्छ्छेद 199 के खण्ड (3) भीर (4) ;

भनुच्छेद 202 के खण्ड (3) का उतना भाग जिलने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के बेतनो और भन्नो से हैं,

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमे य दोनो सम्मिलित है),

भनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक ; भौर अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध शापन सहित रिपार्ट के राज्य क विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने में है;

- (iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्द्वारा भग की जाती है
- (iv) सिवधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का ग्रर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रिपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा ग्रीर उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों ग्रीर उसकी शक्तिया से हैं, ग्रथं, जब तक कि सदर्भ द्वारा ग्रन्था ग्रेपेक्षत ने हो, ससद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा ग्रीर विशिष्टतया अनच्छेद 213 में राज्यपाल ग्रीर राज्य के विधान मण्डल या उसके सदनों के प्रति निदेश का ग्रंथ केमश राष्ट्रपति ग्रीर समद् या उसके सदना के प्रति निदेश लगाया जाएगा
- परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमे ये दोनों सिम्मिलित है), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा । से लेकर पैरा । तक (जिसमें ये दाना सिम्मिलित है) के उपवन्धा पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खड़ के उपखड़ (।) के अधीन उस सीमा तक जहा तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ,
- (v) सिविधान में उस राज्य के विधान मण्डल के या एतद्द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदण का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा व आधार पर समद हारा या राष्ट्रपति या सिविधान के अनच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखड़ (र) में निदिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की णिक्तयों का प्रयोग करत हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है और मैसूर साधारण खण्ड अधिनियम 1899 (1899 का मैसूर अधिनियम—2) और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10वा) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो वह यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,

नीलम सजीव रेड्डी,

31 दिसम्बर, 1977

राष्ट्रपति ।

[स॰ फा॰ 5/11013/33/77-एस० एड पी॰ (डी॰-5)]

न**ई दिल्ली**, ११ दिसम्बर 1977 टी० सी • ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 31st December 1977

G.S.R. 799(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 31st day of December 1977 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Karnataka and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that the State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi,

NEELAM SANJIVA REDDY.

President

The 31st December, 1977

[No. F V/11013/33/77-S&P(DV)]
T C A SRINIVASAVARADAN,Secy

New Dalhi The 31st December, 1977

प्रादेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

सा॰ का॰ नि॰ 799(म्र) —-राष्ट्रपति द्वारा जारी किथा गया निस्नलिखित ग्रादेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है —

भारत के सविधान के श्रनुच्छेद 356 के श्रधीन मेरे द्वारा श्राज दिसम्बर 1977 के 31वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का श्रनुसरण करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता हू कि कर्नाटक राज्य सरकार के सभी कृत्य श्रौर सविधान के श्रधीन पा उस राज्य म प्रवृत्त किसी विधि के श्रधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्यांपणा के खण्ड (क) के प्राधार पर स्वय सम्भाज लिया है, राष्ट्रपति के श्रधीक्षण निदेशन श्रौर नियनण के श्रध्यक्षीन रखने हुए उक्त राज्य के राज्याल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

नई दिल्ली,

नीलम संजीव रेड्डी,

31 दिसम्बर, 1977

राष्ट्रपति ।

[स॰ फा॰ 5/11013/33/77--एस॰ एउ पी० (डी०-5)] टी० सी॰ ए० श्रीनिवासवरदन, सचित्र।

नई दिल्ली,

31 दिसम्बर, 1977

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मृद्रणालय मिन्टी गाँड नई दिल्ली दारा मृद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली दारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY TITE (ENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD NEW DEITH AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977